Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

नवंबर (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- दीपावली पर उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर 3
- मिर्जापुर, सोनभद्र व महराजगंज में बनेगा जनजातीय संग्रहालय 3
- बुलंदशहर के अरविंद ने डबल्स रोइंग प्रतियोगिता मे जीता स्वर्ण पदक 4
- पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक बनीं सौम्या माथुर 5
- पशुधन मंत्री ने किया इटावा में प्रदेश के पहले भेड़-बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण 5
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्स पर देश के दूसरे सबसे चर्चित नेता 6
- प्रदेश में बनाए जाएंगे 35 नए बाल आश्रय गृह 7
- एकमुश्त समाधान योजना 8
- अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड बैठक में पास 9
- पाँच मेडिकल संस्थानों में लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली 10
- 'एकमुश्त समाधान योजना' (ओटीएस) का शुभारंभ हुआ 11
- अयोध्या में कैबिनेट बैठक: धर्म व संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावों पर लगी मुहर 12
- प्रयागराज के सोरांव क्षेत्र में बनेगा औद्योगिक गलियारा 13
- गोरखपुर के ताल कंदला में 27 एकड़ ज़मीन पर बनेगा एक्वा पार्क 13
- नि:शुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ 14
- बाराबंकी की ग्राम पंचायत सिधयावाँ अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा सम्मानित 15
- प्रदेश के किसानों के खाते में भेजी गई 3849 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि 15
- प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी ज़िला जेल प्रयागराज में बनकर तैयार 16
- 8 राज्यों के 131 मेधावियों को श्री डोरीलाल अग्रवाल राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति 17
- निवेश प्रोत्साहन नीति की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी 17
- प्रदेश में 1,600 मेगावाट की अनपरा ई का जल्द निर्माण होगा शुरू 18
- प्रदेश में हलाल लिखे उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध 18
- ग्रेटर अलीगढ़ में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 19
- उत्तर प्रदेश का सालाना सॉफ्टवेयर निर्यात 40 हज़ार करोड़ रुपए के पार 19
- शहरों के बंद पड़े सिनेमाघरों में अब बन सकेंगे बहुमंज़िला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 20
- मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास 21
- मुख्यमंत्री ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को दी हरी झंडी 22
- उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक आयोजित होगा 'संस्कृति उत्सव 2023' 23
- बरेली की आशी को लस्ट स्टोरीज-2 के लिये मिले दो अवॉर्ड 24
- बायोडीजल के उत्पादन, वितरण से संबंधित एड्वांस्ड वेब पोर्टल का विकास 25
- लखनऊ विश्वविद्यालय एकेडमिक ऑटोनॉमी के ग्रेड वन में हुआ शामिल 25
- वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में 28 हज़ार 760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया 26

नोट :

उत्तर प्रदेश

दीपावली पर उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर

चर्चा में क्यों ?

31 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दीपावली पर उज्ज्वला योजना के 1,75,04,385 लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का एलान किया गया है।
- विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया था।
- पहले प्रचलित उपभोक्ता दर से 14.2 किलो का सिलेंडर रिफिल कराना होगा। उसके पाँच दिन के बाद सिलेंडर की राशि उपभोक्ता के आधार प्रमाणित बैंक खाते में ऑयल कंपनियों की ओर से हस्तांतरित की जाएगी।
- यह सुविधा केवल उज्ज्वला योजना के एक कनेक्शन पर मिलेगी। प्रदेश सरकार पर इससे 2312 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।

मिर्जापुर, सोनभद्र व महराजगंज में बनेगा जनजातीय संग्रहालय

चर्चा में क्यों ?

31 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने मिर्जापुर, सोनभद्र और महराजगंज में बनने वाले जनजातीय संग्रहालय के लिये प्रस्तावित ज़मीन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पक्ष में हस्तांतरित करने के केंद्र सरकार के फैसले को अनापत्ति दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियाँ सूचीबद्ध हैं। उनमें भौगोलिक असमानता के साथ-साथ रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान और कला में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। उन्हें संरक्षित करने के लिये मिर्जापुर, सोनभद्र और महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनाया जाएगा।
- जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिये संबंधित ज़िलाधिकारियों द्वारा ज़मीन संस्कृति विभाग लखनऊ को आवंटित की गई है।
- प्रत्येक संग्रहालय के लिये केंद्र सरकार 15 करोड़ रुपए देगी। इसमें राज्य सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा।
- संग्रहालय के लिये मिर्जापुर में अतरैला पांडेय गाँव में 4.046 हेक्टेयर ज़मीन, सोनभद्र में राबर्टसगंज में 2.82 हेक्टेयर ज़मीन और महराजगंज की नौतनवा तहसील में 0.506 हेक्टेयर ज़मीन आवंटित की जाएगी।
- संग्रहालय में जनजातीय जीवन से जुड़ी जानकारियों, सूचनाओं, फिल्मों, चित्रों आदि का प्रदर्शन डिजिटल थियेटर में किया जाएगा। ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा तैयार उत्पादों का विक्रय किया जाएगा।

बुलंदशहर के अरविंद ने डबल्स रोइंग प्रतियोगिता मे जीता स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों ?

1 नवंबर, 2023 को बुलंदशहर ज़िले के अरविंद सिंह ने गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में रोइंग के लाइट वेट मेंस डबल्स स्कल्स में अपने साथी अर्जुन लाल जाट के साथ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि बुलंदशहर ज़िले के खुर्जा थाना क्षेत्र के खबरा गाँव निवासी अरविंद सिंह ने अक्तूबर में एशियन गेम्स में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था।
- अरविंद सिंह वर्ष 2016 से आर्मी में कार्यरत हैं। आर्मी के साथ-साथ वह रोइंग प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग करते हैं।
- अरविंद सिंह रोइंग प्रतियोगिता में विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में भी वह प्रतिभाग कर चुके हैं। वहीं, साल 2021 और 2022 में उन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक और 2023 में रजत पदक अपने नाम किया।

नोट :

पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक बनीं सौम्या माथुर

चर्चा में क्यों ?

1 नवंबर, 2023 को रेलवे बोर्ड की अतिरिक्त सदस्य (वित्त) सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) की पहली महिला महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया।

प्रमुख बिंदु

- पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण का तबादला हो जाने के कारण उनकी जगह पर सौम्या माथुर को कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंज़ूरी के बाद रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया है।
- सौम्या माथुर पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक हैं, 1952 में इसके गठन के बाद अब तक किसी महिला अधिकारी को एनईआर का महाप्रबंधक नहीं बनाया गया था।
- एनईआर की नई जीएम सौम्या माथुर ने भारतीय रेल लेखा सेवा (आईआरएएस) के 1987 बैच के माध्यम से रेल सेवा में प्रवेश किया। पहली नियुक्ति वडोदरा, पश्चिम रेलवे में हुई। इन्होंने पश्चिम, उत्तर एवं मध्य रेलवे में लेखा विभाग के अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर काम किया है।
- इसके अलावा वह अपर मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम रेलवे/मुंबई सेंट्रल, मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे/जयपुर, प्रधान वित्त सलाहकार/मेट्रो रेलवे/कोलकाता तथा प्रधान वित्त सलाहकार/दक्षिण पूर्व रेलवे/कोलकाता जैसे महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं।
- उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक जयपुर के रूप में भी कार्य किया है। इनके कार्यकाल में जयपुर स्टेशन को प्लैटिनम ग्रीन रेटिंग मिला था।
- सौम्या माथुर ने गांधीनगर-जयपुर रूट को पूर्ण रूप से महिला मुख्य लाइन स्टेशन के रूप में भी सफलतापूर्वक संचालित कराया। रेलवे बोर्ड द्वारा बदलाव की पहल के लिये इन्हें बेस्ट चेंज एजेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा इन्होंने जेआईसीए (जापान), आईएनएसईएडी (सिंगापुर) एवं आईसीएलआईएफ (मलेशिया) में उच्च प्रबंधक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।
- उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर रेलवे 14 अप्रैल, 1952 को अस्तित्व में आया था। अवध तिरहुत रेलवे, असम रेलवे और पुरानी बीबी एंड सीआई रेलवे के फतेहगढ़ ज़िले को मिलाकर इसका गठन किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था।
- 15 जनवरी, 1958 को उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे का गठन किया गया। इसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर को बनाया गया। वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे में तीन मंडल हैं, जिनके मुख्यालय वाराणसी, लखनऊ और इज्जतनगर हैं।

पशुधन मंत्री ने किया इटावा में प्रदेश के पहले भेड़-बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

2 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन निदेशालय में वर्चुअल रूप से इटावा में बने प्रदेश के पहले भेड़-बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ भी किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भेड़-बकरी के पालन की प्रदेश में बेहतर संभावनाएँ हैं, जो किसानों व पशुपालकों की आय दोगुनी करने में सहायक होगी। इस केंद्र में इच्छुक लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इस केंद्र में भेड़ एवं बकरी पालकों को वैज्ञानिक तरीके से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- विदित हो कि इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 1 जनवरी, 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय मंत्री उमा भारती द्वारा किया गया था।

नोट :

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्स पर देश के दूसरे सबसे चर्चित नेता

चर्चा में क्यों ?

5 नवंबर, 2023 को सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल 'ट्वीट बाइंडर' द्वारा जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्स पर देश के दूसरे सबसे चर्चित नेता बन गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल 'ट्वीट बाइंडर'की ताजा रैंकिंग के अनुसार अक्तूबर में एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैंडल को लेकर सबसे अधिक चर्चा हुई।
- ट्वीट बाइंडर ने भारत में एक्स यूज़र्स की ओर से 1 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक पोस्ट की संख्या के आधार पर रैंकिंग तैयार की है। संपूर्ण रैंकिंग में पीएम मोदी, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और साउथ के एक्टर विजय ही सीएम योगी से आगे हैं।
- वहीं सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वैश्विक पटल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, अमेरिका और इंग्लैंड तक योगी के प्रशंसकों की बड़ी संख्या है।
- एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2.65 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वहीं, इंस्टाग्राम पर 77 लाख फॉलोअर्स हैं। सीएम योगी के वॉट्सएप चैनल पर भी करीब 15 लाख फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं।

नोट :

प्रदेश में बनाए जाएंगे 35 नए बाल आश्रय गृह

चर्चा में क्यों ?

5 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार घर से भागे हुए, गुमशुदा, तस्करी किये गए, कामकाजी, बाल भिखारियों, मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले बच्चों की देखभाल के लिये प्रदेश में 35 नए आश्रय गृहों का निर्माण कराया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों समेत 19 जनपदों में इन आश्रय गृहों का निर्माण कराया जाएगा। विभाग की ओर से इसके लिये 400 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है।
- विदित हो कि किराये और राजकीय भवनों में संचालित बाल आश्रय भवनों में से अधिकांश की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जर्ज़र भवनों, तंग कमरों, भवनों में खुली हवा व क्षमता के सापेक्ष मूलभूत ढाँचों का अभाव देखते हुए सरकार नए आश्रय स्थलों का निर्माण कराने जा रही है।
- यहाँ खुले हवादार कमरे, योग, व्यायाम, खेलकूद, बागवानी आदि के लिये खुले मैदान होंगे, साथ ही चाइल्ड केयर होम, ऑब्जर्वेशन होम, न्याय बोर्ड, सुपरिंटेंडेंट एवं वॉर्डन के आवास की भी सुविधा होगी।
- महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बालिकाओं के लिये 12 बाल गृह, बालकों के लिये 1 बाल गृह, शिशुओं और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण यूनिट के लिये 6 बाल गृह, किशोरों के लिये 11 संप्रेक्षण गृह व 5 इंटीग्रेटेड होम का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी मंडलों में सभी श्रेणियों का कम-से-कम एक गृह संचालित करेगी।
- प्रस्तावित राजकीय गृहों में शामिल हैं-
  - आगरा में एक बालिका गृह,
  - अलीगढ़ में बाल गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,
  - आज़मगढ़ में शिशु गृह एवं बालिका गृह,
  - प्रयागराज में बाल गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,
  - लखनऊ में एकीकृत आश्रय सदन,
  - बरेली में बालिका गृह, किशोर संप्रेक्षण गृह एवं शिशु गृह,
  - मेरठ में बालिका गृह, किशोर संप्रेक्षण गृह एवं शिशु गृह,
  - सहारनपुर में बालिका गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,
  - मुरादाबाद में बालिका गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,

नोट :

- वाराणसी में एकीकृत आश्रय सदन,
- मिर्ज़ापुर में बालिका गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,
- गोरखपुर में एकीकृत आश्रय सदन,
- बस्ती में बालिका गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,
- झाँसी में बालिका गृह, किशोर संप्रेक्षण गृह एवं शिशु गृह,
- कानपुर में शिशु गृह/विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण,
- अयोध्या में एकीकृत आश्रय सदन,
- देवीपाटन में बालिका गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,
- चित्रकूट में बालिका गृह, किशोर संप्रेक्षण गृह और शिशु गृह,
- अमेठी में एकीकृत आश्रय सदन।

एकमुश्त समाधान योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की ओर से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिये एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) जारी कर दी गई है। यह योजना आठ नबंबर से 31 दिसंबर, 2023 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नबंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा।
- इस योजना के तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी। यह शत-प्रतिशत छूट एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी।
- बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा।
- विदित हो कि प्रदेश में हर साल एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू होती रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओटीएस लागू करने पर जोर दिया था। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन की ओर से ओटीएस योजना जारी की गई है।
- समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की भी सुविधा दी जाएगी।
- योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं।
  - 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  - एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट,
  - 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- इसी प्रकार तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
- तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

नोट :

- निजी वाणिज्यिक संस्थानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
- किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 3 डिफाल्ट (निर्धारित तिथि पर जमा न करने) की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।
- निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च, 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर, 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी।

अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड बैठक में पास

चर्चा में क्यों ?

7 नवंबर, 2023 को अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने बताया कि अलीगढ़ नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा गया, जो पास हो गया है। इस प्रस्ताव को अब मंजूरी के लिये शासन को भेजा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अलीगढ़ नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में भाजपा पार्षद संजय पंडित ने अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा था, जिसका सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया।
- विदित हो कि विगत 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित हिन्दू गौरव दिवस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने भी अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की बात कही थी। पूर्व में ज़िला पंचायत बोर्ड भी अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित कर चुका है।
- गौरतलब है कि प्रदेश में कई रेलवे स्टेशन के भी नाम बदले जा चुके हैं। योगी सरकार में ही मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और झांसी रेल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया था।
- देश में दशकों से शहरों के नाम बदले जाते रहे हैं। हालांकि, नाम बदलने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। किसी शहर का नाम बदलने के लिये पहले नगर पालिका/नगर निगम से प्रस्ताव पास होता है। फिर इसे राज्य कैबिनेट के पास भेजा जाता है। राज्य कैबिनेट में पास होने के बाद नए नाम का गजट जारी होता है। इसके बाद नए नाम की शुरुआत होती है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और देश का एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र है। यहाँ 100 से अधिक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शामिल है।
- अलीगढ़ अपने ताला उद्योग के लिये पूरी दुनिया में मशहूर है। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में निर्यात किये जाते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ अपने पीतल के हार्डवेयर और मूर्तिकला के लिये प्रसिद्ध है।

पाँच मेडिकल संस्थानों में लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

7 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पाँच अस्पतालों में ई-हॉस्पिटल प्रणाली लागू करने के लिये धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश जारी करते हुए बताया कि पारदर्शिता लाने के लिये सचिवालय की भांति प्रदेश के पाँच मेडिकल संस्थानों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रथम चरण में संजय गांधी पीजीआई, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, केजीएमयू, कल्याण सिंह अतिविशिष्ठ कैंसर संस्थान तथा कानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
- कार्यदायी संस्था यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन को जल्द से जल्द कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है।
- उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ई-आफिस एक डिजिटल वर्क प्लेस साल्यूशन है। अभी इसकी शुरूआत प्रदेश के पाँच अस्पतालों से की गई है। प्रयोग सफल होने पर दूसरे मेडिकल संस्थानों में व्यवस्था लागू की जायेगी। इससे उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कामकाज को बढ़ावा मिलेगा।
- इसका मकसद कार्यालय के सभी पत्र, पत्रावली, फाइल का डिजिटलाइजेशन करना है। इससे फाइल व पत्रावलियों को तलाशना आसान होगा। कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। फाइलों के गायब होने की आशंका कम होगी। कम समय में फाइलें खोजी जा सकेंगी।

नोट :

'एकमुश्त समाधान योजना' (ओटीएस) का शुभारंभ हुआ

चर्चा में क्यों ?

8 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ किया। यह योजना 31 दिसंबर, 2023 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लिये पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र निवासी मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल सौंपा।
- 'एकमुश्त समाधान योजना'के तहत राज्य सरकार ने बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों को सहूलियत दी है। उनके बिल पर ब्याज व जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता महज 35 फीसदी जुर्माना भर कर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं।
- इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नबंबर तक, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा।
- इस योजना के तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी। यह शत प्रतिशत छूट एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी।
- बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा।
- योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं।
  - 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  - एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट,
  - 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

नोट :

- तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
- तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- निजी वाणिज्यिक संस्थानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
- निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च, 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्तूबर, 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी।

अयोध्या में कैबिनेट बैठक: धर्म व संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावों पर लगी मुहर

चर्चा में क्यों ?

9 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अयोध्या में हुई कैबिनेट की बैठक में धर्म व संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट की बैठक में 'अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद', 'माँ पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद' और मुज़फ्फरनगर में 'शुकतीर्थ विकास परिषद' के गठन को मंज़ूरी दी गई है।
- कैबिनेट की बैठक में निम्नलिखित अन्य प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली-
  - अयोध्या के माझा जमथरा गाँव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है।
  - अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने के प्रस्ताव को मंज़ूर कर लिया गया।
  - अयोध्या में प्रतिवर्ष होने वाले मकर संक्रांति व बसंत पंचमी मेले, बुलंदशहर के अनूपशहर के कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेले और हाथरस के लक्खी मेला श्री दाऊजी महाराज के प्रांतीयकरण को मंज़ूरी दी गई है। इन मेलों की व्यवस्था में होने वाला खर्च सरकार वहन करेगी।
  - उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन एवं बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई है।

नोट :

- प्रदेश मे महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक मे प्लांट लगाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है।
- ड्रोन पॉलिसी को मंज़ूरी दी गई है।
- राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है।
- शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है।

प्रयागराज के सोरांव क्षेत्र में बनेगा औद्योगिक गलियारा

चर्चा में क्यों ?

12 नवंबर, 2023 को परियोजना के नोडल अधिकारी जगदंबा सिंह ने बताया कि कुंभ नगरी प्रयागराज में यमुना पार में शंकरगढ़ में औद्योगिक गलियारे की बुनियाद रखने के बाद गंगा पार के सोरांव क्षेत्र में एक और औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेस-वे के आसपास के क्षेत्रों में इसकी स्थापना का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। शंकरगढ़ के बाद सोरांव क्षेत्र में बनने वाला यह ज़िले का दूसरा औद्योगिक गलियारा होगा।
- प्रयागराज में यूपीडा की तरफ से एक्सप्रेस वे के आसपास के क्षेत्र में इस औद्योगिक गलियारा को विकसित करने की सरकार की योजना है। गंगा एक्सप्रेस वे से सटे तीन गाँवों को इसके लिये चिन्हित किया गया है। जिन तीन गाँवों को इसके लिये चिन्हित किया गया है, उसमें मलाक चतुरी, जूड़ापुर डांडू तथा बारी सराय लाल शामिल है।
- प्रयागराज के सबसे पिछड़े इलाकों में भी इंडस्ट्रियल हब की स्थापना होगी। प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के यमुना पार इलाके के सबसे पिछड़े इलाके शंकरगढ़ को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने का रोड मैप तैयार किया है।
- उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस इलाके का सर्वे शुरू करने के बाद क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये चयनित भूमि का प्रस्ताव प्रशासन के पास भेजा है। इसके बाद उद्योगों की स्थापना का कार्य शुरू होगा।
- गौरतलब है कि शंकरगढ़ इलाके में इंडस्ट्रियल हब डेवलप करने के लिये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यहां सौर ऊर्जा का प्लांट डालना चाह रहा है जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
- यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष नाथ के मुताबिक इस इलाके की सर्वे प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आगे का कार्य शुरू होगा। इस इलाके में एक ऑयल रिफायनरी की स्थापना का प्रस्ताव भी सरकार के पास है जिसे 2000 एकड़ की भूमि में शंकरगढ़ ब्लाक में स्थापित होना है।
- विदित हो कि शंकरगढ़ के पथरीले इलाके में कृषि योग्य भूमि की कमी और भूमि के उर्वर न होने की वजह से अधिकतर स्थानीय लोगों को शहरों में जाकर अपनी जीविका चलानी पड़ रही है। इलाके में उद्योग स्थापना की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने यहां इंडस्ट्रियल हब बनाने का निर्णय लिया है।
- प्रयागराज के ज़िला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि इलाके की भौगोलिक स्थिति और ऊर्जा के संसाधनों की मौजूदगी से शंकरगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये उपयुक्त इलाके के रूप में देखा जा रहा है। नैनी के बाद ज़िले का यह दूसरा इंडस्ट्रियल हब होगा। यहां औद्योगिक विकास से 10 हज़ार से अधिक रोजगार का सृजन होगा। इससे शहरो में पलायन कर गए स्थानीय लोग भी वापस अपने क्षेत्र में आयेंगे।

गोरखपुर के ताल कंदला में 27 एकड़ ज़मीन पर बनेगा एक्वा पार्क

चर्चा में क्यों ?

13 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर के सदर तहसील के ताल कंदला में एक्वा पार्क बनाया जाएगा, जिसके लिये 27 एकड़ ज़मीन चिह्नित की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना से मछली पालकों को काफी फायदा होगा।

प्रमुख बिंदु

- इस एक्वा पार्क के चालू हो जाने से मछली पालन से जुड़े लोगों को काफी लाभ मिलेगा। एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियाँ तैयार की जाएंगी और मछली के बीज को लेकर शोध होगा। साथ ही यहाँ पर मत्स्य बीज बैंक, मत्स्य पालन, मत्स्य प्रसंकरण से लेकर और कई सुविधा होगी।

नोट :

- गोरखपुर के साथ ही मथुरा में भी एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर के ताल कंदला में पहले पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के लिये जमीन दी गई थी, लेकिन लो लैंड होने से मिट्टी भरपाई का काम अधिक होने के कारण इस जगह को एक्वा पार्क के लिये उपयुक्त पाया गया।
- विदित हो कि गोरखपुर एवं आसपास के क्षेत्र में निषाद समाज के लोगों की संख्या काफी अधिक है। गोरखपुर में एक्वा पार्क खुल जाने से इससे जुड़े व्यवसाय को गति मिलेगी और पास के ज़िलों के मछली पालकों को काफी फायदा होगा।

नि:शुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोकभवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को नि:शुल्क रसोई गैस रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने होली के मौके पर मार्च के महीने में भी फ्री रसोई गैस देने की घोषणा की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- लोकभवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 10 लाभार्थियों को सब्सिडी की राशि के चेक का वितरण भी किया। योजना के शुभारंभ के मौके पर 54 लाख से अधिक परिवारों के लिये सब्सिडी की राशि तेल कंपनियों के खाते में भेजी गई।
- योजना के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने लोक कल्याण संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व संकल्प पत्र में दीपावली व होली में मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, उसी क्रम में इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है।
- नि:शुल्क रसोई गैस सिलेंडर का लाभ प्रदेश के 1.75 करोड़ परिवारों को मिलेगा और सब्सिडी मद में राज्य सरकार 2312 करोड़ रुपए व्यय करेगी।

बाराबंकी की ग्राम पंचायत सिधयावाँ अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

14 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले की ग्राम पंचायत सिधयावाँ को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन-आईएसओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- करीब पांच हजार की आबादी वाले ग्राम पंचायत सिधयावाँ की ग्राम प्रधान हेमलता सिंह के प्रयासों से कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प किया गया जिसके लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला।
- विदित हो कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी ज़िले के नंबर एक ग्राम पंचायत के रूप में सिधयावाँ को 11 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था, जिसका उपयोग अत्याधुनिक पुस्तकालय और आर. ओ. प्लांट लगाने में किया जा रहा है।
- बाराबंकी के गांवों में भी शहर की तर्ज पर विकास कार्य कराए जा रहें हैं और उन्हें मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। यही वह है की इस गांव का चयन मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए हुआ और सीएम योगी ने ग्राम प्रधान को पुरस्कृत कर इनके कार्यों की तारीफ की।
- आरसीसी व इंटरलॉकिंग युक्त सड़कें, चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे, बच्चों को सुंदर परिवेश देने के लिए चिल्ड्रन पार्क, ओपन जिम, सोलर लाइट, घरों में जलापूर्ति के लिए बनाई गई टंकी, कायाकल्प युक्त विद्यालय, ग्राम सचिवालय की स्वच्छता व सुंदरता और 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बन रहा ज़िले का सबसे बड़ा अमृत सरोवर यहाँ के विकास की कहानी बयाँ कर रहा है।

प्रदेश के किसानों के खाते में भेजी गई 3849 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि

चर्चा में क्यों ?

15 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के 1.75 करोड़ से अधिक (175.28 लाख) किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 15वीं किस्त के रूप में 3,849 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी ज़िले से देशभर के 8 करोड़ से अधिक किसानों के लिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के रूप में 18 हज़ार करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के 1.75 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में ये राशि हस्तांतरित की गई।
- प्रदेश के 1.80 करोड़ से अधिक किसानों के भूलेख अंकन, बैंक खाते की आधार सीडिंग एवं
- ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, शेष किसानों के लिये 30 नवंबर तक 15वीं किस्त जारी की जाएगी।
- गौरतलब है कि भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त पाने के लिये लाभार्थियों के भूलेख अंकन, बैंक खाते की आधार सीडिंग व ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है। प्रदेश में 2.26 करोड़ किसानों के भूलेख अंकन, 2.04 करोड़ किसानों के बैंक खाते की आधार सीडिंग व 1.77 करोड़ कृषकों का ई-केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है।

नोट :

- पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक चार माह पर 2000 रुपए की दर से, वर्ष में कुल 6000 रुपए की राशि बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है। यह योजना दिसंबर 2018 में प्रारंभ की गई थी।
- उत्तर प्रदेश में योजना के आरंभ से अब तक 2,62,21,153 किसान इस योजना से कम-से-कम एक बार लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के तहत प्रदेश में किसानों के खाते में अब तक 59,149.69 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है।

प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी ज़िला जेल प्रयागराज में बनकर तैयार

चर्चा में क्यों ?

15 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी ज़िला जेल प्रयागराज के नैनी में बनकर तैयार हो गई है। नैनी सेंट्रल जेल की क्षमता से ज़्यादा रह रहे बंदियों को दिसंबर में इस नई ज़िला जेल में शिफ्ट किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में क्षमता से दो गुना ज़्यादा कैदी बंद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका बोझ कम करने के लिये निर्देश दिये थे, जिसके बाद नैनी ज़िला जेल का निर्माण किया गया है।
- 2800 कैदियों को रखने की क्षमता वाली नैनी की ज़िला जेल प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जेल है। इसे 173 करोड़ रुपए की लागत से कुल 65 एकड़ भूमि पर बनाया गया है।
- इस जेल में बारिश के पानी का संचयन, सीवेज उपचार संयंत्र और यहाँ तक कि महिला कैदियों के छोटे बच्चों के लिये क्रेच की सुविधाएँ भी रहेंगी।
- प्रयागराज की सेंट्रल जेल में 2,060 बंदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन इस जेल में क्षमता से कहीं अधिक 4,263 कैदियों को रखा जाता है। इस जेल को अब दिसंबर से कैदियों के बोझ से राहत मिलने जा रही है। नैनी सेंट्रल जेल से कुछ कैदियों को अब इस नवनिर्मित नैनी ज़िला जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

प्रदेश में 9 ऐतिहासिक धरोहरों को लग्जरी होटल समेत एडैप्टिव रीयूज एसेट्स में बदलने की प्रक्रिया शुरू

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश को पर्यटन के लिहाज से देश का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में प्रदेश की चुनिंदा ऐतिहासिक धरोहरों को लग्जरी होटल सहित एडैप्टिव रीयूज एसेट्स में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्य को अंजाम देने के लिये एजेंसियों के निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कुल 490 करोड़ रुपए के निवेश के जरिये इन ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प किया जाएगा।
- कार्य योजना के अनुसार, लखनऊ के छतरमंजिल, मिर्जापुर के चुनार फोर्ट व झांसी के बरुआ सागर फोर्ट का 100 करोड़ रुपए के निवेश से कायाकल्प किया जाएगा।
- इसी प्रकार, लखनऊ की कोठी गुलिस्तान-ए-इरम, कोठी दर्शन विलास व कोठी रौशन-उद्-दौला में 50-50 करोड़ रुपए के निवेश से कायाकल्प किया जाएगा।
- प्रदेश में मथुरा के बरसाना स्थित जल महल सहित कानपुर देहात के शुक्ला तलाब व कानपुर नगर स्थित टिकैत राय बारादरी को भी 30-30 करोड़ रुपए के निवेश के जरिये एडैप्टिव रीयूज एसेट्स में तब्दील करने की योजना है।
- इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के 10 राही टूरिस्ट बंगलों के भी विकास के लिये लीज आधारित प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन (पीएसपी) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें बाराबंकी के देवा शरीफ, सीतापुर के हरगाँव, शामली के कांढला, एटा के सोरों, बुलंदशहर के खुरजा, अमेठी के मुंशीगंज, एटा के पटना पक्षी विहार, बदायूँ के काछला, मिर्जापुर के चुनार व प्रतापगढ़ के भूपिया मऊ शामिल हैं।

नोट :

- विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों के निवेश के माध्यम से विरासत संपत्तियों को उनका प्राचीन गौरव लौटाने की महत्त्वपूर्ण पहल की गई है। इसी क्रम में, इन स्थानों को वेलनेस सेंटर, हेरिटेज होटल, लग्जरी रिजॉर्ट्स, म्यूजियम, बुटीक रेस्तरां, मैरिज डेस्टिनेशन व वेडिंग वेन्यू, एडवेंचर टूरिज़्म स्पॉट, होमस्टे, थीमपार्क तथा अन्य पर्यटक व अतिथि इकाइयों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

8 राज्यों के 131 मेधावियों को श्री डोरीलाल अग्रवाल राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति

चर्चा में क्यों ?

19 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जेपी सभागार में आयोजित समारोह में अमर उजाला फाउंडेशन और विकलांग सहायता संस्था, आगरा शाखा की ओर से देश के 18 राज्यों के 131 मेधावी दिव्यांग विद्यार्थियों को 22.26 लाख रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई।

प्रमुख बिंदु

- छात्रवृत्ति के लिये 278 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 105 का चयन किया गया। साथ ही 26 उन पात्र विद्यार्थियों को इस बार भी छात्रवृत्ति दी गई, जिन्हें गत वर्ष दी गई थी।
- बीटेक के 24, बीए के 22, बीएड के 21, एमए के 13, डीएड 11, पीएचडी, बीएससी के छह-छह, एमबीबीएस, एमएड व एलएलएम के चार-चार, एमबीए के तीन, बीकॉम, एमकॉम व बीफार्मा के दो-दो, एमएससी, पीजीडीसीए, एमएसडब्ल्यू, डिप्लोमा इन लैब, बी.लिब, एमबीए, एलएलबी के एक-एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- इनके अलावा, छात्रवृत्ति पाकर किसी मुकाम तक पहुँच चुके राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रह्लाद चौहान एवं डॉ. एश्वर्या गुप्ता को भी सम्मानित किया गया।
- संस्था के सचिव अनिल अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 1985 से छात्रवृत्ति दी जा रही है। वर्ष 1989 से अमर उजाला के संस्थापक व मुख्य संरक्षक डोरीलाल अग्रवाल की स्मृति में यह सेवा प्रकल्प शुरू किया गया। अब तक 3000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है।
- संस्था के उपाध्यक्ष सुनील विकल ने बताया कि एक वर्ष में एक करोड़ रुपए तक की छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य रखा गया है।

निवेश प्रोत्साहन नीति की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी

चर्चा में क्यों ?

20 नवंबर, 2023 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और फार्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिये बनाई गई निवेश प्रोत्साहन नीति (एफडीआई पालिसी) की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी।

प्रमुख बिंदु

- जारी एसओपी के अनुसार यह एफडीआई पालिसी एक नवंबर 2023 से 31 अक्तूबर, 2028 तक प्रभावी रहेगी।
- फार्च्यून 500 में फार्च्यून ग्लोबल 500 और फार्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को शामिल किया गया है।
- निवेशकों को पाँच साल बिजली के बिल में सौ फीसदी छूट तथा स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण में 50 से 100 फीसदी छूट मिलेगी। इसके अलावा ज़मीन पर भी 75 से 80 फीसदी तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
- निवेशकों को स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण में छूट गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में 50 फीसदी, मध्यांचल, पश्चिमांचल में 75 फीसदी और बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 100 फीसदी होगी। सब्सिडी के एवज में निवेशक को उतनी ही रकम की बैंक गारंटी देनी होगी।
- विकास प्राधिकरणों से ज़मीन लेने पर स्टांप छूट के लिये शासन द्वारा निवेशक को एक पत्र दिया जाएगा। निजी डेवलपर से ज़मीन खरीदने पर इनवेस्ट यूपी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इसी के आधार पर सब्सिडी मिलेगी। औद्योगिक उत्पादन शुरू होने के बाद स्टांप व पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

नोट :

- एफडीआई के तहत निवेशकों को ज़मीन पर न्यूनतम 75 फीसदी से 80 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। कुछ मामलों में ये 80 फीसदी से भी ज्यादा हो सकती है। इसकी समीक्षा सात दिन के अंदर इनवेस्ट यूपी के सीईओ की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति करेगी। इस रिपोर्ट को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के नेतृत्व में गठित प्राधिकार समिति के सामने पेश किया जाएगा।
- समिति 15 दिन में प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर देगी। प्राधिकार समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार होने पर संबंधित विकास प्राधिकरण के लिये पत्र जारी किया जाएगा। यदि निवेशक दी गई निवेश अवधि के अंदर उत्पादन शुरू नहीं करता है तो 12 फीसदी ब्याज के साथ ज़मीन वापस ले ली जाएगी।
- सब्सिडी प्राप्त करने के लिये जरूरी लेटर आफ कम्फर्ट को निवेशकों को कंपनी से जुड़े 11 दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।
- निवेश के लिये अवधि-
  - 100 से 200 करोड़ रुपए के निवेश में उत्पादन अधिकतम 4 साल में शुरू करना होगा।
  - 200 से 500 करोड़ रुपए के निवेश में उत्पादन अधिकतम 5 साल में शुरू करना होगा।
  - 500 से 3000 करोड़ रुपए के निवेश में उत्पादन अधिकतम 7 साल में शुरू करना होगा।
  - 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश में उत्पादन अधिकतम 9 साल में शुरू करना होगा।

प्रदेश में 1,600 मेगावाट की अनपरा ई का जल्द निर्माण होगा शुरू

चर्चा में क्यों ?

20 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम बोर्ड की बैठक में प्रदेश में 1,600 मेगावाट की नई उत्पादन इकाई अनपरा ई के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। अब इसे शासन को भेजा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अनपरा ई इकाई के निर्माण में लगभग 18,624 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसे एनटीपीसी और उत्पादन निगम लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड के तहत स्थापित किया जाएगा।
- विदित हो कि अभी तक अनपरा में चार इकाइयाँ हैं। इनमें से तीन इकाइयाँ उत्पादन निगम की हैं, जिसकी क्षमता 2630 मेगावाट है। वहीं 1200 मेगावाट की एक इकाई लेंको कंपनी की है।
- पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बताया कि ओवरा सी की 660-660 मेगावाट और जवाहरपुर की 660-660 मेगावाट की नई इकाइयाँ हैं। इन दोनों जगह एक-एक इकाइयों में जल्द ही विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं दोनों जगह की एक-एक इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं। इसी तरह पनकी की 660 मेगावाट की एक इकाई भी गर्मी के दिन में बिजली उत्पादन करने लगेगी।

प्रदेश में हलाल लिखे उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

18 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश में किसी भी उत्पाद पर हलाल प्रमाणन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी खाद्य उत्पाद के साथ ही दवाओं पर भी लागू होगी।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निरंतर निगरानी के निर्देश दिये गए हैं।
- खाद्य उत्पाद के साथ ही दवाओं के उत्पाद के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हालाँकि विदेश भेजे जाने वाले उत्पाद के लिये छूट रहेगी।
- विदित हो कि विदेश में निर्यात होने वाले मांस और उससे निर्मित उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र जारी होता रहा है। धीरे-धीरे तेल, साबुन, घी सहित सभी उत्पादों पर हलाल प्रमाणन की मुहर लगने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद इसे रोकने की रणनीति बनाई गई और 18 नवंबर को इस पर प्रदेश में पाबंदी लगा दी गई है।

नोट :

- प्रदेश में हलाल प्रमाणन वाले किसी भी खाद्य उत्पादों एवं दवाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई उत्पादन हलाल प्रमाणन वाला पाया गया तो संबंधित निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्माण के साथ ही भंडारण, वितरण, विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- यदि राज्य में कार्यरत कोई निर्यातक अपने खाद्य उत्पाद अथवा दवा को उन देशों के लिये तैयार करता है, जहाँ हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पाद ही स्वीकार किये जाते हैं तो उसे छूट दी जाएगी। वह दूसरे देश के लिये तैयार होने वाले उत्पाद का निर्माण, भंडारण एवं वितरण कर सकेगा।
- प्रदेश की नियमावली में हलाल प्रमाणीकरण का कोई नियम नहीं है। सिर्फ गुणवत्ता, पैकिंग, लेबलिंग सही होनी चाहिये। नए आदेश के बाद यदि कोई हलाल प्रमाणीकरण युक्त दवाओं, प्रसाधन सामग्री व खाद्य सामग्री तैयार करता है अथवा भंडारण व वितरण करता है तो उसके खिलाफ अधिनियम 1940 व तत्संबंधी नियमावली के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
- इसके तहत तीन साल का कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना, और नियम 18 ए के तहत छह साल का कारावास अथवा 25 हज़ार का जुर्माना हो सकता है।

ग्रेटर अलीगढ़ में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम

चर्चा में क्यों ?

18 नवंबर, 2023 को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि बनारस की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) अलीगढ़-पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 300 हेक्टेयर में आवासीय योजना विकसित कर रहा है। इसमें ग्राम मूसेपुर, जिरौली, जिरौली डोर, अटलपुर, अहमदाबाद, जतनपुर चिकावटी, रुस्तमपुर अखन, ल्होसरा बिसावन में जमीन ली जा रही है।
- लखनऊ की कंसलटेंसी फर्म द्वारा टाउनशिप का ले-आउट तैयार किया गया है। टाउनशिप तीन चरणों में विकसित की जा रही है। टाउनशिप में करीब छह एकड़ जमीन पर स्टेडियम का निर्माण होगा।
- इस स्टेडियम को बनारस के स्टेडियम की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित इस स्टेडियम में करीब 20 हज़ार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रिंकू सिंह अलीगढ़ से हैं। ऐसे में इस स्टेडियम के बनने से ताला एवं तालीम के इस शहर का नाम देशभर में और भी चमकेगा और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को उच्चकोटि की सुविधाओं वाला खेल मैदान भी उपलब्ध हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश का सालाना सॉफ्टवेयर निर्यात 40 हज़ार करोड़ रुपए के पार

चर्चा में क्यों ?

- 21 नवंबर, 2023 को आईटी मंत्रालय के अधीन काम कर रहे सॉफ्टवेयर टेक्नॉलजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के अपर निदेशक डा. प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि लगातार बढ़ रहे सॉफ्टवेयर निर्यात में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। प्रदेश का सालाना सॉफ्टवेयर निर्यात 40 हज़ार करोड़ रुपए को पार कर गया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2020-21 में प्रदेश का सॉफ्टवेयर निर्यात सालाना 28 हज़ार करोड़ रुपए था जो इस समय 40 हज़ार करोड़ रुपए के पार चला गया है। इसमें लखनऊ का हिस्सा 400 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 550 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है। प्रदेश भर से हार्डवेयर का निर्यात भी 1500 करोड़ रुपए के पार चला गया है।

नोट :

- एसटीपीआई के अपर निदेशक डा. प्रदीप कुमार द्विवेदी के मुताबिक एनजीआईएस (नेशनल जेनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम) योजना के तहत 42 नए स्टार्ट अप तैयार किये गए हैं। इनमें से आठ को 25-25 लाख रुपए फंड दिया गया है। इसके अलावा लीप अहेड प्रोग्राम में एक करोड़ रुपए तक फंड देने की तैयारी है।
- इस योजना में फंड के अलावा छह माह तक 30 हज़ार रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।
- सॉफ्टवेयर स्टार्टअप शुरू करने का सबसे बढ़ा लाभ युवाओं को हुआ है। आईटी मंत्रालय की एनजीआईएस (नेशनल जेनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम) के तहत हर क्षेत्र में स्टार्टअप तैयार किये जा रहे हैं। देश में 12 स्थानों पर इस योजना के तहत केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और प्रयागराज में दो केंद्र हैं जिनके ज़रिये स्टार्ट अप तैयार किये जा रहे हैं।
- नई आईटी नीति लागू होने के बाद इस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। विशेष रूप से चिकित्सा जगत में सॉफ्टवेयर के प्रयोग के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का अहम प्रयोग लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआईएमएस) में शुरू हुआ है।
- एसजीपीजीआई प्रबंधन और एसटीपीआई के इस साझा कार्यक्रम में क्लीनिकली ट्रायल पर लगातार काम किया जा रहा है। एसटीपीआई ने हाल ही में 28 ऐसे स्टार्टअप तैयार कराए हैं जो केवल चिकित्सा जगत में सॉफ्टवेयर तकनीक पर प्रयोग कर रहे हैं। इनमें से छह तो अपने उत्पादों को पेटेंट भी करा चुके हैं।
- इस समय प्रदेश में एसटीपीआई के पांच सेंटर लखनऊ, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज और मेरठ में हैं। जबकि अन्य चार सेंटर आगरा, गोरखपुर, बरेली और वाराणसी में प्रस्तावित हैं।
- वर्तमान में एसटीपीआई पार्कों से 342 एक्सपोर्ट यूनिट जुड़ी हैं। 101 कंपनियाँ इंक्युबेशन सेंटर से जुड़ी है। एसटीपीआई के चार और सेंटर शुरू होंगे तो युवाओं के लिये रोज़गार के नए मार्ग खुलेंगे। एक ही पार्क से छह हज़ार से ज्यादा युवाओं को तत्काल फायदा मिलता है।

शहरों के बंद पड़े सिनेमाघरों में अब बन सकेंगे बहुमंज़िला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

चर्चा में क्यों ?

- 23 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वर्षों से बंद पड़े सिनेमा हॉल के संचालकों को बहुमंज़िला कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दे दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- आवास विभाग के विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी ने राज्यकर विभाग की सहमति के बाद इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है।
- अब ऐसे सिनेमा हॉल की जमीन पर मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग के आधार पर बहुमंज़िला कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकेगा। नक्शा पास करने से पहले मनोरंजन कर से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
- विदित हो कि प्रदेश में करीब 800 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर बंद हो चुके हैं और लगभग 150 बंद होने के कगार पर हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर अधिकांशत: शहर के पुराने सघन इलाकों में स्थित है।
- सिनेमा हॉल के बंद होने के बावजूद इसकी जमीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे सिनेमा हॉल मालिक के साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इन स्थितियों को देखते हुए सरकार ने सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल की जमीन पर बहुमंज़िला भवन बनाने की अनुमति दी है।

मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 24 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने गोरखपुर को 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने गोरखपुर में 175 करोड़ रुपए लागत की 116 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किये हैं।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 145.67 करोड़ रुपए की लागत से हुए 82 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 29.61 करोड़ रुपए की लागत से 34 विकास कार्यों का शिलान्यास किये है। शिलान्यास के कार्यों में 63 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना भी शामिल है।
- इन परियोजनाओं का किया गया लोकार्पण-
  - योजना निधि से पत्रकारपुरम् एवं राप्तीनगर- 4940.60 लाख
  - प्राधिकरण, एचयूआरएल, अवस्थापना योजना मद- 4973.35 लाख
  - इलेक्ट्रिकल वर्क प्राधिकरण भवन, पैडलेगंज, बुद्ध द्वार, बाबा गंभीरनाथ- 0216.06 लाख
  - त्वरित आर्थिक विकास योजना 2021-22- 1430.05 लाख
  - त्वरित आर्थिक विकास योजना 2022-23- 3006.73 लाख

नोट :

- इन परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास-
  - परिषदीय विद्यालयों के लिये (जोन-1 से 5)- 0599.83 लाख
  - परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, सामुदायिक भवन, ईवी चार्जिंग स्टेशन- 1323.96 लाख
  - प्राधिकरण की अवस्थापना निधि के अंतर्गत 8 कार्य- 1037.06 लाख
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और यहाँ उन्होंने गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना की ई-लाटरी भी निकाली।

मुख्यमंत्री ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को दी हरी झंडी

चर्चा में क्यों ?

- 27 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर आफ एक्सीलेंस के निर्माण को हरी झंडी दी है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव 5 दिसंबर, 2023 को रखी जाएगी। यहाँ पर 5जी को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) से जोड़ने और 6जी पर रिसर्च किया जाएगा।
- टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। इस पहल से दूरसंचार के क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोज़गार भी मिलेगा।
- सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य टेलीकॉम के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर उसे बढ़ावा देना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च और विकास के केंद्र के रूप में काम करेगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मदद तो मिलेगी ही, साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिये समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलेगी।
- टेलीकॉम का कहाँ-कहाँ समुचित प्रयोग किया जा सकता, इस पर प्रमुख फोकस रहेगा। इसमें ई-लर्निंग, ई-एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सैटेलाइट सेंटर को अपग्रेड करने पर काम किया जाएगा।
- 5जी को एआई से जोड़ा जाएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के नये-नये डिवाइस को विकसित किया जा सके। यह सहारनपुर को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फर्मों से निवेश आकर्षित करने और इनोवेशन व आंत्रप्रेन्योरशिप के लिये मज़बूत ईको सिस्टम बनाने में सक्षम करेगा।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5जी और 6जी टेक्नोलॉजी के विकास में योगदान देगा, जिससे भारत विदेशी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करने और ग्लोबल मार्केट में कंप्टीशन बढ़ाने में सक्षम होगा।
- यह टेलीकॉम के क्षेत्र में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिये मंच के रूप में भी कार्य करेगा। यह छात्रों, रिसर्च और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और स्पेशल स्किल हासिल करने के अवसर प्रदान करेगा।
- इन सेक्टर्स पर होगी रिसर्च-
  - एडवांस वायरलेस कम्युनिकेशन के फंडामेंटल
  - 5जी और वायरलेस स्टैंडर्स
  - मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर मॉड्यूल डिजाइन
  - वायरलेस कम्युनिकेशन के लिये एआई/एमएल
- ये होंगे फायदे-
  - स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड पेटेंट
  - लास्ट माइल एक्सेस
  - दूरस्थ या कम सेवा वाले क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड पहुँच
  - सेलुलर बैकहॉल

नोट :

- स्टोरेज एरिया नेटवर्क
- डिजास्टर मैनेजमेंट
- नेटवर्क इनेबल्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स
- डिफेंस और सिक्योरिटी
- एयरोस्पेस एविएशन/सैटेलाइट कम्युनिकेशन
- वर्चुअल रिएलिटी
- स्मार्ट सिटी
- स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग
- ई-हेल्थकेयर

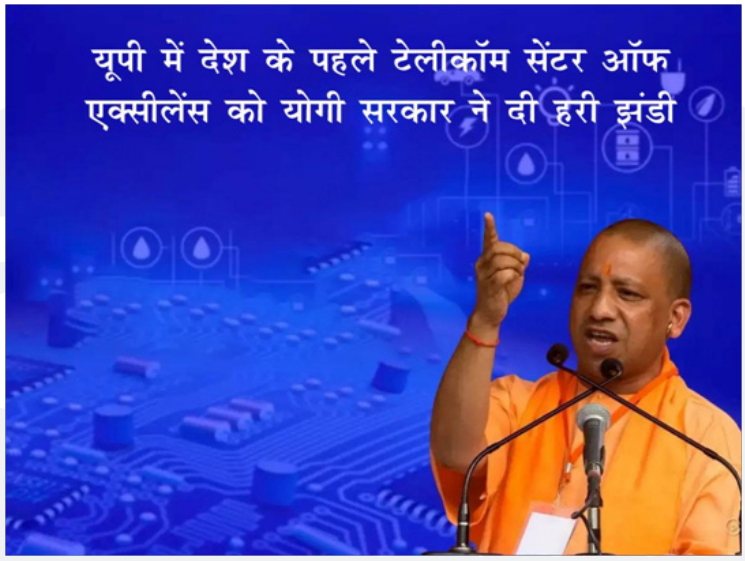

उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक आयोजित होगा 'संस्कृति उत्सव 2023'

चर्चा में क्यों ?

- 28 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोककला को देश सहित दुनियाभर में प्रसिद्धि दिलाने के लिये प्रदेश में 25 दिसंबर से 26 जनवरी, 2024 तक 'संस्कृति उत्सव 2023' का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 'उत्तर प्रदेश पर्व: हमारी संस्कृति-हमारी पहचान' थीमलाइन से आयोजित किये जा रहे इस उत्सव से गाँव, ब्लॉक, तहसील, ज़िला, मंडल सहित राज्य स्तर पर लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित मंच मिलेगा।
- संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इस उत्सव का आयोजन प्रदेश भर में कराया जाएगा, जिसमें कई प्रतियोगिताएँ शामिल होंगी।
- मुख्य रूप से शास्त्रीय, उप-शास्त्रीय, लोकनाट्य व लोकसंगीत जैसी सांस्कृतिक विधाओं को प्रश्रय प्रदान करने की भावना से इन कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा।
- इस आयोजन में ग्रामीण अंचलों में प्रचलित लोक संगीत को भी काफी प्रमुखता दी जाएगी तथा सभी स्तरों पर होने वाली प्रतियोगिताओं में विजेता कलाकारों को सम्मानित व पुरस्कृत किया जाएगा।

नोट :

- 25 से 30 दिसंबर के बीच तहसील मुख्यालय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गाँवों, पंचायत, ब्लॉक व तहसील स्तर के कलाकार भाग लेंगे। इसके बाद 1 से लेकर 5 जनवरी, 2024 के बीच ज़िला मुख्यालयों पर होने वाली प्रतियोगिता में तहसील स्तर के चयनित कलाकार भाग लेंगे।
- मंडलीय मुख्यालय स्तर पर 10 से 15 जनवरी के बीच प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें ज़िला स्तर पर चयनित कलाकार प्रतिभाग करेंगे। इसके आगे तीन अन्य चरणों से गुजर कर प्रतियोगिता निर्णायक स्थिति में पहुँचेगी और इन तीनों ही चरण की प्रतियोगिताओं का आयोजन लखनऊ में होगा। मंडल स्तर के चयनित कलाकारों को अभ्यास व मुख्य आयोजन में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा और सम्मानित भी किया जाएगा।
- आयोजन के अंतर्गत शास्त्रीय गायन में ख्याल, ध्रुपद, उप-शास्त्रीय गायन में ठुमरी, दादरा, चौती, चौता, झूला, होरा, टप्पा, वादन में बाँसुरी, शहनाई, हारमोनियम, सितार, वॉयलिन, गिटार, सारंगी, वीणा, तबला, पखावज, मृदंगम व घटम तथा जनजातीय व लोक वाद्ययंत्र से जुड़ी प्रतियोगिताएँ होंगी। वहीं, नृत्य में कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम व अन्य शास्त्रीय नृत्यों से जुड़ी प्रतियोगिताएँ होंगी।
- इसी प्रकार, लोकनृत्य में धोबिया, अहिरवा, करमा, शैला, डोमकच, आखेट तथा लोकनाट्य में नौटंकी, रामलीला, रासलीला, स्वांग, भगत, बहुरूपिया, नुक्कड़ नाटक आदि की प्रतियोगिताएँ होंगी।
- लोकगायन में कजरी, चौती, झूला, बिरहा, आल्हा, निर्गुण, लोकगीत, कव्वाली व सुगम संगीत के अंतर्गत गीत, गजल, भजन तथा देशभक्ति गीत जैसी कैटेगरीज़ में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
- एकल नृत्य व सामूहिक नृत्य के लिये रिकॉर्डेड संगीत मान्य होगा। प्रतियोगिताओं में विजयी कलाकारों को मेडल, प्रमाण-पत्र व स्मृति चिह्न देकर पुरस्कृत किया जाएगा।

बरेली की आशी को लस्ट स्टोरीज-2 के लिये मिले दो अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बरेली की आशी को मुंबई में आयोजित फिल्मफेयर अवार्ड-2023 में लस्ट स्टोरीज-2 के लिये बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार मिला है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि जनकपुरी निवासी आशी वर्ष 2008 में आशी मुंबई गई थीं। वर्ष 2013 में बॉम्बे टॉकीज से उन्होंने खासी पहचान मिली। उसके बाद लगातार आशी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। अपनी कंपनी के माध्यम से वह कई लोगों को रोज़गार भी दे रही हैं।
- आशी ने निर्माता के तौर पर कालाकांडी, लस्ट स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं। लस्ट स्टोरी-2 की चार कहानियों को करण जौहर, अनुराग कश्यप, जोया अख्तर और दिबाकर बनर्जी ने निर्देशित किया है।
- गौरतलब है कि इससे पहले इस सीरीज की पहली फिल्म लस्ट स्टोरीज को ऐनी अवॉर्ड मिल चुका है।

बायोडीजल के उत्पादन, वितरण से संबंधित एड्वांस्ड वेब पोर्टल का विकास

चर्चा में क्यों ?

- 28 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार बायोडीजल के उत्पादन, भंडारण, क्रय व वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये एक अत्याधुनिक व विशिष्ट पोर्टल का विकास कराएगा।

प्रमुख बिंदु

- यह पोर्टल कई खूबियों से लैस होगा तथा बायोडीजल के उत्पादन, वितरण, एनओसी क्लियरेंस, लाइसेंस आवंटन, पंजीयन, वाद निस्तारण तथा भुगतान संबंधी कार्यों की पूर्ति के लिये 'वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म' की तरह कार्य करेगा।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के प्रयोग के लिये नए आधुनिक वेब पोर्टल का विकास यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड कराएगा। नया पोर्टल बायोडीजल के उत्पादन व वितरण से संबंधित एनओसी व लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया सरलता के साथ पूर्ण करने में सक्षम होगा।
- उल्लेखनीय है कि वेब पोर्टल के विकास का कार्य प्राप्त करने वाली सॉफ्टवेयर एजेंसी को उसके डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन और ऑपरेशनल ट्रेनिंग के साथ ही एनओसी व लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के दौरान मदद करनी होगी।
- यह वेब पोर्टल काफी विस्तृत होगा तथा हिंदी व इंग्लिश माध्यम में कार्य करेगा। इसमें यूपीनेडा के अधिकारियों समेत पब्लिक ऑफिसर्स के लॉगिन और ज़िलाधिकारियों के लॉगिन तथा कार्य योजनाओं की मॉनिटरिंग समेत कई फीचर्स होंगे। इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर बायोडीजल को लेकर राज्य सरकार की नीतियों समेत कई अन्य अहम जानकारियां व विवरण भी शामिल होंगे।
- पोर्टल को इस तरीके से बनाया जाएगा कि वह निवेश मित्र के साथ इंटीग्रेट होकर कार्य करने में सक्षम हो। वेबसाइट में एप्लिकेंट रजिस्ट्रेशन, एप्लिकेशन अप्रूवल, एनओसी मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल, रीन्यूअल मॉड्यूल, क्वेरी सब्मिशन, रिपोर्टिंग मॉड्यूल, एसएमएस व ई-मेल इंटीग्रेशन, क्लाउड सर्वर, सिक्योरिटी ऑडिट, हेल्पडेस्क मॉड्यूल तथा वेब सर्वर डोमेन के लिये एसएसएल जैसे फीचर्स होंगे।
- इसमें एक डैशबोर्ड होगा, जिसमें एप्लिकेंट लॉगिन, मैनुफैक्चरिंग यूनिट, रीटेलर यूनिट जैसे लॉगिन इंटरफेस रहेंगे। यह रिस्पॉन्सिव डिजाइन टेक्नोलॉजी आधारित होगा। इसका डेटा ट्रांसफर बैंडविड्थ 1000 गीगाबाइट प्रति सेकेंड होगा, जबकि 500 गीगाबाइट तक डिस्क टू डिस्क बैकअप स्टोरेज की सुविधा से लैस होगा। इसके साथ ही, इसमें लाइव टेलिकास्टिंग की सुविधा भी रहेगी।
- यह वेब पोर्टल यूजर फ्रेंडली होगा तथा इसके जरिए त्वरित वाद निस्तारण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय एकेडमिक ऑटोनॉमी के ग्रेड वन में हुआ शामिल

चर्चा में क्यों ?

- 28 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने लखनऊ विश्वविद्यालय को श्रेणी-1 के विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। इससे विश्वविद्यालय तय शर्तें पूरी करके ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यकम शुरू कर सकेगा। इसके साथ ही उसे अगले स्तर की शैक्षणिक स्वायत्तता भी मिल पाएगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यूजीसी की ओर से मान्यता प्राप्त श्रेणी-1 का संस्थान बनने के बाद अब लखनऊ विश्वविद्यालय यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 और समय-समय पर हुए संशोधनों के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने पर आयोग की मंज़ूरी के बिना मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड में पाठ्यक्रम शुरू कर सकता है। साथ ही यूजीसी की मंज़ूरी के बिना संबंधित विषयों में नए कोर्स, कार्यक्रम, विभाग और केंद्र शुरू कर सकता है।
- इसके अलावा विश्वविद्यालय यूजीसी को जानकारी देकर नए डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कोर्स शुरू करने, भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंदर ऑफ-कैंपस केंद्र खोलने, कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने, अनुसंधान पार्क-ऊष्मायन केंद्र-विश्वविद्यालय समाज संबंध केंद्र खोलने, विदेशी संकाय को नियुक्त करने, कुल संख्या के मुकाबले 20 फीसदी से ज्यादा विदेशी छात्रों को प्रवेश देने जैसे निर्णय ले सकता है।
- लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने कहा कि श्रेणी-1 संस्थानों को अधिक शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है, जो उन्हें अपने पाठ्यक्रम को डिजाइन करने, प्रशासनिक निर्णय लेने, नवीन कार्यक्रम शुरू करने, विदेशी संकाय नियुक्त करने और वर्तमान संकाय को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाती है।
- डीन एकेडमिक प्रो. गीतांजलि मिश्रा ने कहा कि डीन विश्वविद्यालय पहले से ही ट्विनिंग, संयुक्त और दोहरी डिग्री और ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा जैसे यूजीसी नियमों के अनुरूप नए अभिनव कार्यक्रम शुरू कर रहा था। श्रेणी-1 का दर्जा मिलने के बाद किसी भी नई शुरुआत के लिये औपचारिकताओं की संख्या कम हो जाती है।
- विदित हो कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने नैक में ए प्लस-प्लस ग्रेड मिलने के बाद दूरस्थ और ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव यूजीसी को भेजा था। इसमें स्नातक और परास्नातक दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम शामिल हैं। दूरस्थ और ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये नैक में सर्वोच्च रैंक की जरूरत होती है। अब जब विश्वविद्यालय को श्रेणी-1 का दर्जा मिल गया है तो उसे पाठ्यक्रम शुरू करने में कोई अड़चन नहीं आएगी।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में 28 हज़ार 760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया

चर्चा में क्यों ?

- 29 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का 28,760.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अनुपूरक बजट में नई योजनाओं के लिये 7421.21 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 1946.39 करोड़ रुपए राजस्व खर्च के लिये और 9714 करोड़ रुपए पूंजी खर्च के लिये रखे गए हैं।
- अनुपूरक बजट में की गई घोषणाएँ:
  - राज्य सरकार ने 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' के लिये 2000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है।
  - 'पीएम मित्र योजना' के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क की स्थापना के लिये 510 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।
  - उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति के क्रियान्वयन के लिये 100 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।

नोट :